P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-4* July - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

आर्थिक एवं श्रम क्षेत्र पर कोविड–19 प्रभाव : महिलाओं के विशेष संदर्भ में अध्ययन

Covid-19 Impact on Economic and Labor Sector: A Study with Special Reference to Women

Paper Submission: 12/07/2020, Date of Acceptance: 26/07/2020, Date of Publication: 28/07/2020

सुनील बाजपेयी
प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शासकीय तिलक महाविद्यालय,
कटनी, मध्य प्रदेश, भारत

पूर्णिमा मिश्रा
शोध छात्रा,
वाणिज्य विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर, मध्य प्रदेश, भारत

आर.एस.त्रिपाठी
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
बड़वारा, कटनी, मध्य प्रदेश,
भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र पूरी दुनिया में फैले कोविड–19 संक्रमण के प्रभावों का सामाजिक–अर्थशास्त्रीय अध्ययन है। महिलायें प्रवासी मजदूरों के रूप में सबसे अधिक परिवार की बेरोजगारी और साधनहीनता बढ़ने की षिकार हैं। प्रवजन की स्थिति पूरे देश में कारखाने, खेत और श्रम के विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्र में अवसर खोने की कहानी कहती है। गरीब परिवार की महिलायें स्व–सहायता समूहों के जरिये परिवार की आमदनी के लिये प्रयास कर सकती हैं, जैसे उदाहरणों से देखा गया है। कोविड–19 के दौर में महिला आर्थिक सष्शक्तिकरण के सामने नयी स्थिति और अवसरों की तलाश इस धीमी गति में फँसे आर्थिक विकास में करनी होगी।

The research paper presented is a socio-econometric study of the effects of Kovid-19 infection spread across the world. Women as migrant laborers are the biggest victims of increasing family unemployment and resourcelessness. The state of migration tells the story of lost opportunities in various informal sectors of factory, farm and labor across the country. Women from poor families can strive for family income through self-help groups, as seen in the examples. In the era of Kovid-19, the new situation and opportunities in front of women economic empowerment will have to be explored in this slow economic development.

मुख्य शब्द : कोविड–19, प्रवासी मजदूर, स्व–सहायता समूह, अनौपचारिक श्रम क्षेत्र, लॉकडाउन, शहरी रोजगार।
Covid-19, Migrant Laborers, Self-Help Groups, Informal Labor Sector, Lockdown, Urban Employment.

प्रस्तावना

भारत की 49% आबादी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है तथा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में भारत अभी विकासशील अवस्था में है। कभी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की विकास दर विगत वर्ष 2018–19 में 4.7% रही जो कि पिछले 6 वर्षों में विकास दर की सबसे निचली स्तर है तथा वर्ष 2019 में भारत में बेरोजगारी 45 वर्षों के सबसे अधिकतम स्तर पर थी। भारत में असंगठित क्षेत्र करीब–करीब 94% आबादी को रोजगार देता है तथा अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 45% है।

महामारी कोविड–19 की वजह से असंगठित क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह संक्रमण ऐसे वक्त में फैला जब भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी की सुस्ती से उबरने का प्रयास कर रही थी।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र द्वैतीयक आकड़ों पर केन्द्रित विश्लेषण है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, महिला रोजगार और प्रवजन के कारण व्याप्त आर्थिक संकट की ओर ध्यान दिलाया गया है। शोध में संदर्भ समाचार पत्रों, इंटरनेट से लिया गया है। इसमें विवरणमूलक पद्धति ली गयी है।

साहित्यावलोकन

महामारी कोविड–19 या कोरोना वायरस का समाज अर्थव्यवस्था पर गंभीरतम असर हुआ है। स्टीव मैथ्यूवान एवं कैट हपेज ने इसका विस्तार से अपने शोध पत्र में विश्लेषण किया है। समाज में आर्थिक त्रासदी से फैली अराजकता का विस्तार हो चुका है कि अवसाद से बढ़ती आत्महत्या चिंताजनक

है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जन–स्वास्थ्य पर आयोजित हुई थी जिसमें सामाजिक वैज्ञानिकों ने कोविड–19 के प्रभावों और खतरों पर चर्चा की थी (पॉल आर वार्ड, 2020)। नये सामाजिक सिद्धांतों और अर्थशास्त्री नियमों का समय आ गया है। कोविड–19 के संक्रमण के दौर में आर्थिक दृष्टि से महिलाओं के स्वास्थ्य, नौकरी आदि पर कोविड–19 का बड़ा असर है। बड़े–बुजुर्गों एवं क्रिटिकल बीमारियों से महिलाएं जो समस्या का सामना करती है, उससे उनके जीवन में खतरे और बढ़े हैं। आर्थिक एवं सामाजिक खतरे कोविड–19 के प्रभावों से पूरी दुनिया आज घिरी हुई है। लाखों की मृत्यु एवं आर्थिक मंदी ने घेरा बढ़ा दिया है। आर्थिक रूप से आज का समाज जोखिम समाज बन गया है।

आर्थिक प्रश्नों पर प्रभात पटनायक ने कोविड–19 के प्रभाव का अध्ययन किया है जो आर्थिक गणितीय मॉडल से विवेचन किया गया है, जिसमें लॉकडाउन की वृहत आर्थिक दशाओं की विवेचना भी है। महिलाओं और श्रमिकों पर कोविड–19 के प्रभावों का विश्लेषण कई विद्वानों ने किया है। अचानक लॉकडाउन और तालाबंदी से मजदूरों का प्रवजन अपने गांव से सपरिवार होता गया रोजगार प्रवजन, पुनः काम की तलाश तथा प्रवासी मजदूरों और उनके सपरिवार पलायन से पूरे भारत में अफरा–तफरी बनी रही। गांवों में पहुंचते–पहुंचते प्रवासी महिलाएं परिवार के साथ त्रासदी और तकलीफें झेलती रही। इकोनॉमिक टाइम्स : जनवरी, 2019 ने बेंगलुरु के प्रवासी महिलाओं के दुख का वर्णन किया है। अनैच्छिक प्रवास से महिलाओं ने सबसे अधिक परिवार के पलायन तथा पैसे की तंगी का सामना किया। रंजीता महंती ने नगरीय अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस के असर को लॉकडाउन के दौरान मजबूर महिलाओं का सर्वेक्षण किया था।

महिलाओं और श्रमिकों के पलायन और लॉकडाउन पर पत्रकारों, आर्थिक विश्लेषकों ने व्यापक रूप से लेखन कार्य किया है जो इस क्षेत्र में प्राथमिक शोध हेतु प्रगत आधार कहा जा सकता है आदिति राठौर (2020) एवं पत्रलेखा चटर्जी (2020) आदि।

भारत में मार्च, 2020 से पहले कोविड–19 संक्रमण का असर सफेदपोश पेशे वालों की बढ़ती बेरोजगारी का ग्राफ ऊंचा उठा है, जो साप्ताहिक श्रम आंकड़ों में श्रम भागीदारी दर, बेरोजगारी दर और रोजगार दर के बड़े अनुपात में दर्ज होते रहे हैं। यह उम्र, लिंग, व्यवसाय, धर्म, जाति के आंकड़े हैं जो अप्रैल 2020 में 12. 1 करोड़ नौकरियों के खत्म होने से आई बेरोजगारी थी। CMIE के उपभोक्ता पिरामिड सर्वे के दौरान के (20 वॉ चक्र) वेतन भोगी रोजगार में गिरावट के संकेत मिले। सफेदपोश व्यवसाय में महिलाएं लाखों की संख्या में वेतन भोगी थी। डॉक्टर, इंजीनियर, लेखाकर्म कार्यालय जैसे सफेदपोश पेशेवर व्यवसाय में महिलाएं लॉकडाउन के चलते नौकरी से घर पर बैठ गई। उद्योगों में 20% स्थान महिलाओं ने कोविड–19 प्रभाव से खोया बेरोजगारी दर 21.1% तक पहुंच गई है महिलाओं की स्थिति शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था और राजनीतिक भागीदारी सूचकांक लिए जाते हैं इसका कोरोना वायरस संकेत निराशाजनक है आर्थिक अवसरों की समानता बड़े पैमाने पर बिछड़ गई है 2011 12 में 33.1% महिला आश्रम भागीदारी थी जो 2017-18 में 7.8% से घटकर 25.3% रह गई। नियोक्ता और कार्यों का शारीरिक महत्व भी महिलाओं को पीछे रख देता है। गिरावट चारों ओर मुख्य क्षेत्रों में दर्ज हुई है, जैसे –

1. औद्योगिक कंपनियों में रोजगार से बाहर,
2. वित्त, लेखा–सेवा क्षेत्र से बाहर,
3. स्वागत (रिसेप्शनिस्ट) और सूचना प्रौद्योगिकी तक गिरावट,
4. विमान चालक से लेकर वाइन परोसने वाले तक,
5. होटल, जिम, मॉल, ब्यूटी पार्लर, विमानन के अन्य सेवा प्रदाय क्षेत्रों में महिला रोजगार की कमी का बढ़ते का जाना।

समाजशास्त्रीय नजरिए से देखा जाए तो कोविड–19 का असर पुरुष पेशेवर कर्मियों की तुलना में महिलाओं पर अधिक हुआ। उनके पायदान पर पहुंचने के लिए अधिक मेहनत महिलाओं को करना होती है। महिलाओं में बेरोजगारी की दर पुरुषों की तुलना में 3% ज्यादा थी। आज अमेरिका में मंदी चरम पर है। अर्थव्यवस्था में मंदी जी.डी.पी. के गिरते स्तर पर पहुंच गई है और पेशेवर वर्ग का मिडिल क्लास उपभोग आमदनी में सिकुड़न पैदा हो गई। लॉकडाउन के कारण इसमें तेजी आई है।

आकलन करने का क्षेत्र है कि –

1. रोजगार हमेशा के लिए खो देने वाला वर्ग,
2. पुराने काम पर मंदी के बाद लौट जाने वाले,
3. जो रोजगार की आस लगाए हुए हैं।

उभरते आर्थिक क्षेत्र के ठहराव की स्थिति बन गई है इसमें कोविड–19 का प्रभाव देखा गया है। OECD के इकोनॉमिक्स सर्वे में कहा गया है कि भारत में पुरुष और महिलाओं की बेरोजगारी दर के बीच 52% की गहरी खाई है। वैसे भारत में कामगारों के व्यापक आंकड़ों के संग्रह में कमी है।

मजदूरों (श्रम क्षेत्र) का जो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, बड़ी संख्या में पलायन हुआ, ऐसे में बड़ी व छोटी कंपनियों को पुनः उत्पादन में समस्या आयी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मजदूर घर को वापस जा रहे हैं दबाव बढ़ेगा, वहां उनके पास आय के स्रोत कम हैं और घरेलू कृषि या छोटे–मोटे कार्य को करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने में वक्त लगेगा। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र में गिरावट का असर तृतीयक क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ेगा। वहां नौकरियों का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है।

विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा है कि भारत के परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। यहां की अर्थव्यवस्था में 50 फीसदी जी.डी.पी. अनौपचारिक क्षेत्र से आता है और इस महामारी व लाकडाउन की वजह से यह क्षेत्र काम नहीं कर सकता। इसके साथ प्रवासी कामगारों का मुद्दा अहम है। चौथे चरण के लाकडाउन के बाद सभी सेक्टर में थोड़ा–थोड़ा काम ही शुरू हुआ है जैसे ही बड़े पैमाने पर कार्य उद्योग प्रारंभ होंगे मजदूरों एवं कामगारों की बड़ी

समस्या आएगी। यहां कुछ बड़े सेक्टर और उद्योग नागरिकों के आंकड़ों से इसे समझा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 5 करोड़ कामगार काम करते हैं। (बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) जिसमें अकेले महाराष्ट्र में ही 50 लाख लोग इसमें शामिल हैं। 3 करोड़ कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से आकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में काम करते हैं, जिनमें कुल 35% ही मौजूद हैं, बाकि अपने गांव लौट चुके हैं।

'इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन' ने कहा कि कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट ही नहीं रहा बल्कि यह एक बड़ा लेबर मार्केट से जुड़ा आर्थिक संकट खड़ा है। कोविड–19 के संक्रमण में भारत के 11 महानगर इसकी चपेट में है जो देश की शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तीन उच्च उद्योग और विकसित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैं। 80% प्रवासी मजदूरों की खपत यहां के काम कारखानों में होती है। प्रति व्यक्ति आय के मामलों में उत्तर भारतीय राज्य गरीब है और इसी गरीबी के कारण प्रवजन होता है। भारत की तस्वीर बैंकिंग, वित्त और मनोरंजन की है, मुंबई इन तीनों का घर बना हुआ है। झुग्गी झोपड़ी का बड़ा रहवास मुंबई के धारावी में है, जहां संक्रमण के अधिक केस हुए हैं, यहां सामुदायिक संक्रमण का डर है जो कहा जा रहा है जुलाई, 2020 में चरम पर होगा। सामाजिक दूरी यानि 2 गज की दूरी इस घनी आबादी में पालन होना मुश्किल है। यह देखा गया कि भारत के जो राज्य उच्च शहरीकृत हैं वहां कोविड–19 का संक्रमण अधिक हुआ और तेजी पर है। महाराष्ट्र की 12 करोड़ की आबादी का शहरों 7 करोड़ का हिस्सा बसने का 65% के आस पास है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट (17 जून, 2020) कहती है कि 25 शहरों में कुल संक्रमण के 95% मामले दर्ज हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी से भारत की शहरीकृत अर्थव्यवस्था नये पूंजीवादी उपायों से भी पूंजी की प्रधानता को संभालने में सफल नहीं हो पाई है। दुनिया में सन् 1930 में अमरीकी आर्थिक मंदी की याद आती है। इन कारणों पर जाएं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में 'इनबिल्ट प्रेसर' है –

1. आर्थिक सुधारों पर कमजोर अमल,
2. कमतर आर्थिक वृद्धि दर,
3. राज्यों की बढ़ती देनदारी, कर्जे और कैश फ्लो की समस्या,
4. बाजार में मांग में भारी गिरावट एवं पूर्ति की डगमग स्थिति।

यह आशंका जाहिर की गई है कि वायरस संक्रमण में रोकथाम सफल नहीं हुई तो अर्थव्यवस्था में गिरावट आनी तय है। अभी से राजस्व घाटा टालना या कम करना मुश्किल हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण आने वाले तीन महीनों में भी व्याप्त रहेगा, जिसके दौरान खेती का अधिक काम रहता है लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था थमी तो सरकारी राजस्व में भी भारी कमी आई। सरकार के राजस्व को 21,412 करोड़ प्राप्त हुए, जो 2019 अप्रैल की प्राप्ति में 70% पीछे है।

कोरोना संक्रमण से प्रवासी मजदूर, रेहड़ी, पटरी वालों असंगठित क्षेत्र की आर्थिक क्षमता पर सबसे बड़ा प्रभाव रोज की कमाई का सिलसिला लाकडाउन से 3 महीने रुका रहा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर) योजना है जो सूक्ष्म ऋण सुविधा के तहत 10,000 का ऋण देने की है परंतु 14 मई, 2020 को घोषित योजना के लिए सर्वे एवं पात्रता कठिन है। प्रवासी मजदूरों को नगद सहायता, आवास ऋण सहायता जैसे कामों को तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी है। खेतिहर किसानों को भी नगद सहायता, आवास ऋण सहायतायें और जो तत्काल राहत दें और खाते में पैसे पहुंच जाएं। राज्यों ने भी 500 या 1000 तक की सहायता खातों में प्रत्येक किसानों को डाली है। लेकिन गांव में सूदखोर सक्रिय हैं, किसानों के पास जोखिम पूंजी नहीं बची है कि वे आगे बढ़कर खेती में पूँजी लगायें।

व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था की नजर से 15 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत भी है, जिसका अर्थव्यवस्था के विकास की गति 4 या 5 प्रतिशत तक ही रहेगी। अभिजीत बैनर्जी (नोबल) का कहना है कि लोगों को नगदी सहायता देना होगा। प्रत्येक परिवार को कम से कम 5000 रू. देने की जरूरत है अर्थात गरीब आबादी की मदद के लिए सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जाए। इस पर 65 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) का फायदा है, जो प्रवासी मजदूर और निम्न आय वर्ग को दिया जाए। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' का आकलन है कि महामारी ने सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। इसमें पहली तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1.5% से 2.8% के बीच वृद्धि दर रहेगी (अप्रैल 12, 2020)। 1991 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा। विश्व बैंक के आकलन का हवाला से संकेत है। घरेलू निवेश में सुधार की देरी है। कोविड–19 की वजह से घरेलू आपूर्ति और मांग को प्रभावित होने के चलते 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 1.5% से 2.5% रह जाएगी। बाहरी उपायों से वित्तीय मजबूती और मौद्रिक नीति पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। 2021-22 तक के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के प्रभाव से कमजोर या पंगु हालत में पहुंच गई है। जो सुझाव आए हैं वे स्थाई रोजगार कार्यक्रमों को चालू करने या राहत कार्य (फूड फॉर वर्क जैसे मनरेगा सहित) के लिए चालू करें दूसरे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक उद्यम क्षेत्र में श्रम गहन रोजगार प्रक्रियाओं को बढ़ाना।

असंगठित मजदूरों के 40 करोड़ कामगारों के सामने आर्थिक रूप से लाकडाउन बड़ा झटका साबित हुआ है। स्वरोजगार, दिहाड़ी मजदूर सबके सामने पुनः प्रवजन, स्थाई रोजगार जैसे प्रश्न है। मध्यम वर्ग और शहरी मध्यम वर्ग द्वारा थाली पीटने और रोशनी के जरिए कोरोना भगाने से यह प्रश्न सामने आता है कि डूबती अर्थव्यवस्था निर्धनता में वृद्धि करती है। इससे बेरोजगारी दर 7% से 24% में तब्दील हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नकारात्मक वृद्धि पिछले 2 माह (अप्रैल एवं मई, 2020) में नकारात्मक रही और ग्रामीण मजदूरी और उपभोग में लगभग ठहराव आया है। भारत के वित्त बाजार, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक देनदारियों और कर्ज का जाल तथा अपनी

फर्म को दिवालिया दिखाने वाले कारपोरेट हैं। यहॉ कारपोरेट कर्ज का असर है, जैसे–यष बैंक की कर्ज और डूबंत की स्थिति प्रत्यक्ष है।

भारत में टेस्टिंग अभी 52 लाख लोगों की हो पाई है। टेस्टिंग अधिक होने पर संक्रमण रेट और बढ़ेगा। अमेरिका में 2.26 करोड़ लोगों का टेस्ट, रूस में 1.4 करोड़ लोगों का टेस्ट, ब्रिटेन में 60 लाख लोगों का टेस्ट, भारत में 52 लाख और स्पेन में 46 लाख लोगों का टेस्ट हुआ। भारत सातवें क्रम में आगे बढ़कर दुनिया का चौथा संक्रमित देश के स्थान पर पहुंच गया। जून (10.06. 20) के आकड़े यही कहते हैं।

महामारी और महिलाएं

कोरोना वायरस महिला और पुरुषों में भेद क्यों करता है ? यह प्रश्न सामने आता है, आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या दोगुना है। पश्चिमी यूरोप के देशों में 65% पुरुष मरने वालों में थे और अन्य अधिक प्रकोप झेलने वाले देशों में भी पुरुषों की जान का नुकसान अधिक हुआ है। पहला सर्वमान्य कारण यह है कि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों की तुलना में बेहतर होती है। पुरुषों का नशा सेवन या इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। महिलाएं जो नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ में काम कर रही हैं, उनको संक्रमण हो रहा है, जैसे पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजेशन आदि भी इनके लिए अपर्याप्त स्टाक के कारण संक्रमित हो जाना सामने आया है। इनको जोखिम में पाते हैं। अपने परिवार से दूरी, घर की देखभाल के लिए महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते पूरी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जिन देशों में मुखिया महिलाएं हैं, वहां संक्रमण पर नियंत्रण अधिक बेहतर ढंग से हुआ है, जर्मनी, ताइवान, नार्वे, आदि देशों में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो उनको पढ़ाना, घर में मनोरंजन के लिए साधन बनाना, मोबाइल एडिक्शन पर नियंत्रण और डिप्रेशन से निपटना पड़ता है। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। बेरोजगारी चारों तरफ बढ़ रही है। मंदी का हाल होगा तो महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह संकट में आयेगी। अमेरिका में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरी ज्यादा गई। मार्च महीने (2020 वर्ष) के अधिक बेकारी महिलाओं में थी, उन्हें घर बैठना पड़ गया है। विनिर्माण सेवा और घरेलू अर्थव्यवस्था से महिलाएं बाहर होती जाएंगी तो देश का व्यवसायिक यंत्र और आर्थिक ढांचा का अधिक भार पुरूष झेलेंगे। पर्यटन, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, महिला प्रधान कारखानों में मंदी और वायरस के चलते काम के अवसर खो रहे हैं।

दुनिया में महिलाएं समान कार्य समान वेतन का भेदभाव पूर्ण स्थिति का सामना करती हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण सामने है, श्वेत महिला के वेतन से 15 से 20% कम वेतन अश्वेत महिलाएं पाती हैं। बच्चों की देखभाल का अलग दबाव है। अकेले अमेरिकी समाज में दो करोड़ लगभग औरतें बच्चे को परिवार मोर्चे पर कामकाज संभालती हैं, स्पष्ट है महामारी और आर्थिक मंदी बढ़ रही है तो अधिक नुकसान महिलाओं का होगा और संक्रमण के प्रभाव भी। रिसर्च बताती है कि कोरोना महामारी के दौर में मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि हो गई थी और गर्भवती महिलाएं की स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर पड़ रही थी। स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक इस्तेमाल और गर्भपात, पूर्व प्रसव सुविधा और चाइल्ड केयर की सुविधाएं नीचे घटकर महिलाओं के जीवन के जोखिम को बढ़ाती हैं। लॉकडाउन में अधिक गर्भधारण की संभावना का कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में अनुमान किया जा रहा है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, आत्महत्या में वृद्धि, कोविड–19 के दौर में बढ़ी। ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर क्लेयर वेन्हम टीम ने जीका वायरस और इबोला वायरस के संक्रमण की महामारी में महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था पंगु होने का अध्ययन किया है। यह भी अनुमान है कि 90 लाख तक महिलाएं गर्भनिरोधक और गर्भपात सेवाओं से वंचित रहेंगी। कोविड–19 का असर उम्रदराज महिलाओं पर जोखिम बढ़ाने वाला हैं। इनके संक्रमण में आ जाने और मृत्यु जोखिम अधिक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहले से कहता आ रहा है कि महामारी के आंकड़े, आयु, प्रजाति लैंगिक आधार पर तैयार किए जाएं, जिससे सबसे प्रभावित समूह की पहचान होने में सरलता हो, लेकिन ऐसे आंकड़ों की कमी आ जाती है। वैसे तो कोविड–19 का संक्रमण समाज के सभी वर्गों पर है परंतु विशिष्ट सामाजिक समूहों में उनकी गरीबी, परिवार तक सीमित जीवन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पीछे अदृश्य रहने का संबंध महामारियों के चपेट में आने से ध्यान देने योग्य है। भारत में महिलाएं अपने कमजोर स्वास्थ्य और आर्थिक पराधीनता के कारण अधिक प्रत्यक्ष शिकार हो रही हैं। इटली देश के नेशनल हेल्थ डाटा में सर्वे से दर्ज किया गया है कि महामारी के आंकड़े महिलाओं के संबंध में कम है। 70% आंकड़ों का एकत्रीकरण पुरुषों द्वारा 70% तक केंद्रित किया गया है।

वैश्विक स्वास्थ्य में लैंगिक असमानता के जो आंकड़े जुटाए गए हैं उनमें स्थिर संकेतकों का क्रम महिला जनसंख्या पर अधिक कहर ढाने वाला पाया गया। पुरूष नशा सेवन, धूम्रपान, नशेड़ीपन की आदती हैं। महिलाओं की तुलना में जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। एक दूसरा समांतर दृश्य है कोरोना बनी माई (मदर गॉडेस) और महामारी को दूर करने के लिए महिलाएं कर रही हैं पूजा (स्थान– पटना, जून 6, 2020)। यह अंधविश्वास उपज गया है वहां, जहां स्त्री स्वास्थ्य के मानक कमजोर शिक्षा और रोजगार में पीछे हैं। गांव की महिलाएं सामूहिक रूप से गांव के भीतर तालाब, जलाशयों के पास कोरोना देवी की पूजा करने में लगी हैं। पूजा में प्रयुक्त सात सामान, गड्ढे खोदकर महिलाएं उसमें गुड़ के शरबत के साथ इलायची, लौकी के फूल तथा 7 लड्डू रखकर पूजा कर रही है। इससे उन्हें महामारी के खत्म होने की पूर्ण उम्मीद है। यह किसी महिला के सपने में आया जन इतिहास है जो देहात (बिहार) की सभी जाति, वर्ग में एक जैसी मान्यता से माना जा रहा है। लोगों की आस्था और विश्वास का मनोविज्ञान व्यापक कोरोना के पीछे एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचने की खबर है। 'कोरोना देवी' की कल्पना के पीछे भारत में लंबे समय से चमत्कार, स्वयं सिद्ध संत और संतों के तथाकथित चमत्कार और उपदेश का भय है। अशिक्षितों में कोरोना

दैवीकृत आपदा है। जब ईश्वर चाहेंगे तभी प्रकोप दूर होगा।

UNFPA के आंकड़े बताते हैं कि 70 लाख गर्भधारण का खतरा है जो लॉकडाउन में असुरक्षित प्रजनन स्थिति से होगा। निम्न आय वर्ग वाले विशेष तौर पर परिवार नियोजन के साधनों से वंचित रहेंगे और उनके हिंसा, परिवार मारपीट, शोषण की घटनाओं में कोई कमी नहीं। दैनिक मजदूरी वाला परिवार पालने में घर से बाहर अधिक रहेगा क्योंकि रोजी–रोटी और शारीरिक परेशानी में रोजाना संघर्ष करना होता है। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के पहले हफ्ते और 25 अप्रैल तक मारपीट और महिला हिंसा की घटनाओं में 7 गुना वृद्धि हुई थी। लगभग 92 हजार हिंसा की शिकायतें दर्ज हुई (न्यूजक्लिक : 16.06.2020)। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता बढ़ी है। मनोविकृति, अवसाद, तनाव, पैनिक अटैक का फैलाव है तो महिलाएं इससे अधिक प्रभावित है। खाद्य सुरक्षा, नगद पैसे का ट्रांसफर महिलाओं को दिया जा रहा है। 20 करोड़ महिलाओं को 2 हजार करोड़ की राशि महिलाओं को उनके खाते में भेजी गई। पूरे देश में इसको जारी किया गया। ध्यान से देखें तो अनिश्चितता, तनाव, सुरक्षा, भ्रांतियों, आदि से जनता में घबराहट फैली है, इसके आगे बढ़ने का लक्षण है। लंबे समय तक यौन हिंसा की महिलाएं पीड़ित हालातों का गवाह बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं को समान विकास कार्यों मनरेगा और कौशल सृजन के कामों से जोड़ने का प्रस्ताव नया है। महिलाओं को मास्क बनाने का प्रशिक्षण पूरे देश में आज चल रहा है। इसमें भ्रम यह फैलाया जाता है कि जो बोरिया–बिस्तर समेट कर आया है उसको देहात में सुरक्षा देना होगा। बिहार में देखें तो बहुत से समूह मुख्यमंत्री योजना से उम्मीद लगाये रखे हुए हैं, सभी को कोरोना खतम हो जाने के बाद समस्याएं हल करनी होंगी। स्वास्थ्य उपकरणों के लिये मास्क बनाने हेतु महिलाओं के स्वयं समूह चिन्हित और आगे मास्क बनाने में लगे हैं (न्यूजक्लिक : कोरोना वायरस और महिलाओं पर बढ़ती घरेलू हिंसा)।

राजस्व संग्रह कम होना, इससे व्यय के प्रावधानों के लिए उपलब्ध राशियॉ कम होंगी जो महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सुरक्षा कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय करने की प्रवृत्ति है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में राजस्व कराधान के उद्देश्य एवं कल्याण कार्यक्रमों में अधिक प्रावधानित रहते हैं। अतः इस तरह से भी महिला कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय प्रावधान में कमी का नकारात्मक असर पड़ेगा। कोविड–19 के कारण यह प्रकट हुआ है कि महिलाएं रोजगार घटने से प्रभावित होंगी। कर संग्रह जून, 2020 में 76% तक व्यक्तिगत कर एवं 63.9% निगमित कर संग्रह में दर्ज किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष के 70% आकड़े तक कम है।

राजस्व संग्रह अर्थव्यवस्था की मजबूती या गिरावट का मामला है, यह कमजोर वर्ग और संकट में फंसे व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की चिंता को बढ़ा देता है। भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से 'हेल्थ इमरजेंसी' का अंदेशा है। विनिर्माण और कंस्ट्रक्शन वर्क के क्षेत्र में पुरुषों को अवसरों या रोजगार की अधिकता है। इसका बंद पड़े रहना परिवार अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख देगा। लॉकडाउन के प्रभाव नकारात्मक देखे गये। प्रोफेशनल महिलाएं संस्थानों में कार्य से बाहर बैठा दी गई है। बड़ी–बड़ी नौकरियां एक झटके में जा रही हैं। काम पाने के अवसर पुरुषों और महिलाओं के सामने बदल रहे हैं, नौकरियां दूसरे परिदृश्य की ओर ले जाएंगी।

यह कहा गया है कि भारत को अधिक से अधिक कोविड टेस्ट, क्वारंटाइन और राज्यों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र में सीलिंग करने तथा कोविड–19 अस्पताल तैयार करने की प्राथमिकता देना है। महिलाएं संक्रमण के सामने सीमा तक बचाव करने में कामयाब हुई हैं। महिलाएं सस्ता मास्क बना रही हैं अर्थात श्रम के सस्ता करण का मुद्दा अधिक मायने रखता है।

पूरी दुनिया में जांच करने का स्तर भिन्न है। अमेरिका में जांच अधिक जबकि भारत में इसकी अपेक्षा कम है। जो जांच का दायरा है उसमें महिलाएं कम है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को महिलाओं की जांच में तेजी लाने का निर्देश देना चाहिए। प्रसव के दौरान और प्रसव उपरांत माता और उत्पन्न बच्चा दोनों संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि संक्रमित (पॉजिटिव) माँ स्तनपान नहीं कराने को मजबूर हो गई।

कोरोना संक्रमण में और अधिक तेजी आने की संभावना है। यह घोषणा करने वाले यदि महिलाओं की इम्युनिटी मजबूत होने की बात करें यह स्थिति या कहना उचित नहीं है। कोविड–19 का संक्रमण महिला–पुरुष दोनों वर्ग को घातक असर करेगा और लड़ाई भी उतनी ही बड़ी है। महिलाओं के सामने घर और प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। आजीविका कमाने में पटरी–रेहड़ी के कामगार, ठेला लगाने वाले मजदूरों में स्त्रियों की संख्या आधे से कम नहीं है अपितु घर से खाली होकर साग–सब्जी, मनिहारी जैसे छोटे धंधों में महिलायें शहरों में हाट बाजार या हाकर्स जोन में भी मिलती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को छोटी दुकानदारी या रेहड़ी पटरी पर दुकानदारी में पूँजी के लिये 10 हजार का ऋण (सब्सिडी–10%) की घोषणा की गयी है, क्योंकि कोविड–19 के असर से परिवारों की आजीविका को बचाना है।

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को अधिक से अधिक स्व सहायता समूह बनाने के लिए सरकारी मदद देने की घोषणा (14.06.2020) की है। इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए 2020–21 में 1,433 करोड़ रुपए के कार्य दिलाए जाने की योजना है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने गांव एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का निर्माण करें। उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में सरकार उनकी मदद करेगी। मध्यप्रदेश में स्व–सहायता समूहों से जुड़ी 10 लाख महिलाएं हैं, विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि का भी आयोजन अनुसार बजट दिया जाएगा। कार्य भी तय किए गए क्षेत्र निम्न किये गये है।

-	गणवेश बनाने का कार्य	–	400 करोड़,
-	आजीविका विकास	–	65 करोड़,
-	मुर्गी पालन, भेड़ पालन,	–	12 करोड़,
-	90 हजार पी.पी.ई. किट बनाने हेतु	–	41.56 करोड़,
-	टेक होम राषि तैयार करने	–	700 करोड़,
-	गौशाला, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, खेत तालाब भेड़ बागान वृक्षारोपण आदि कार्य के लिए प्रावधान	–	252 करोड़

दैनिक भास्कर, 14.06.2020

इस तरह कोविड–19 की महामारी के प्रभावों का असर देखने के लिए जेंडर गैप मानदंडों से समझना जरूरी है। शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार और उनकी महिलाएं संक्रमण की गिरफ्त में हो रही है इसमें तालाबंदी के बाद कोई अलग प्रवृत्ति नहीं मिली। अलगाव (आइसोलेशन) और क्वारनटाइन की नीति तथा लॉकडाउन के प्रभाव देखे जाए। इसी दौरान महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा और लिंग आधारित शोषण के नए पहलू सामने आए। विशेषकर परिवार पलायन में सड़कों पर सूटकेस पर बच्चे को लिटाए पैदल दिल्ली से बिहार को निकलते प्रवासी मजदूरों की भीड़ में महिलाएं भी कम नहीं थीं। महिलाओं के आर्थिक जीवन को तहस–नहस करने में कोविड–19 के दीर्घकालिक प्रभाव मिलेंगे। अवैतनिक कार्य, घर बैठने, कौशल और पेशेवर कामों से बाहर होना है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ गरीब मजदूर कल्याण योजना 15 जून, 2020 से शुरू हुई है जो प्रवासी मजदूरों के 6 राज्यों में सीधे लागू होनी है और इसमें महिलाओं की मजदूर गिनती करने को सावधानी से काम करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं, राहत के कार्य, टूटी हुई गृहस्थी का सीधा संबंध महिलाओं से है जो वापस गांव लौटकर सामना करेगी। उदाहरण के लिए लखनऊ में चिकन कारीगरी में महिला समूह का भी योगदान है परंतु पूंजी का अभाव और उत्पाद बिक्री की स्थिति चिंताजनक है। अजीविका का संकट है तथा अर्थव्यवस्था में गिरावट लगातार आंकी जा रही है। आज मनरेगा योजना की अहमियत बढ़ गई है, परंतु गांव में महिलाएं इसमें मजदूरी करने में पीछे रहेंगी जैसा आंकड़ों से पुष्ट हो जाता है। रोजगार गारंटी योजना महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं है। गांवों में खेतिहर मजदूरों की संख्या और उन्हें काम मिलने का सिलसिला लगातार घटता जा रहा है। इसमें महिलाओं को घर का काम अधिक है इस कारण से वह काम में नहीं जा पाती।

प्रवासी मजदूरों हेतु 50 हजार करोड़ की योजना आई है। गरीब कल्याण रोजगार योजना यह देश के 6 राज्यों में जहां से श्रमिक प्रवास करते हैं। 116 जिलों को मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान से चुना गया, जाहिर है महिला प्रवासी श्रमिक परिवार के स्तर पर काम करेगी। गांव में महिलाओं के लिए रोजगार की पहली शर्त उनको गांव में ही काम मिले, लेकिन महिला स्व–सहायता समूह के लिए काम का निर्धारण भी क्षेत्रीय और निकट होना चाहिए। इस योजना में 125 दिन का काम मनरेगा से अलग होगा। यह प्रवासी मजदूर के कौशल दक्षता का विषय है, जो प्रवासी मजदूर अपने गांव में कर सकते हैं। गांव में प्रवासी मजदूरों को काम देने के 25 कार्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। असंगठित क्षेत्र में कार्य की समस्याएं स्थानीय स्तर पर हैं। प्रवजन, मौसमी प्रवास, दीर्ध कालीन प्रवजन का लंबा इतिहास है। परिवार को छोड़कर प्रवासी मजदूर घर में पत्नी को रूकने की बाध्यता भी थी। कोविड–19 संक्रमण काल में यह पता चल रहा है कि प्रवजन स्थल से पूरी गृहस्थी लेकर गांव में वापस लौट आए हैं। यह वापसी महिलाओं के जीवन में आर्थिक त्रासदी से कम नहीं होगी। इनको वैकल्पिक आजीविका की जरूरत है।

कोरोना को अवसर में बदलना है, यह कथन महिलाओं ने पंजाब में चरितार्थ किया। पंजाब में लोगों की मदद के लिए 647 सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जा रहे हैं। इनमें ऐसी महिलाएं हैं जिनके पतियों की नौकरी प्राइवेट जॉब के चलते जा चुकी है। 3573 महिलाओं ने 2 महीने में मास्क बनाकर 25 लाख रुपए कमाए। अकेले पंजाब के भटिंडा जिले में 198 महिला सदस्यों ने 3 लाख रूपय कमाया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन को लॉकडाउन अवधि में सक्रिय किया गया और विभिन्न संस्थाओं को जैसे मंडी बोर्ड, स्टेट बैंक, पी.एस.पी.सी.एल. पुलिस को 1500 मास्क बनाकर दिए। पतियों की नौकरी छूटी तो पत्नियों ने मोर्चा संभाला।

झारखंड में भी रांची के नामकम में महिलाएं मास्क बनाकर परिवार की मदद कर रही हैं। उन्हें अब पीपीई किट के लिए भी कार्य मिलने लगा है। उनका तैयार माल अस्पतालों को सप्लाई होने लगा है। आत्म निर्भरता का यह उदाहरण महिला स्वावलंबन का प्रमाण है, जहां 150 से 200 रू. रोज कमाना हालात को संभालने के लिए काम आया। यह तभी आगे बढ़ेगा जब सरकार इनका साथ दे।

एक दूसरे सर्वे से पता चला कि दक्षिण गुजरात में घरों में काम करने वाली महिलाओं की बचत में 43 प्रतिशत कमी आई है और 236 महिलाओं (सूरत, नवसारी, वलसाड) के ऊपर औसत 84 हजार रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है। इसमें 30% महिलाएं घर का काम करके परिवार चला रही हैं। 19% के पास अपना बैंक अकाउन्ट तथा 4% के पास स्वयं का आधार कार्ड नहीं। 32% महिलाएं अनपढ़ हैं और 51% प्राथमिक, 17% माध्यमिक तक पढ़ी हैं। इनमें प्रायः सरकारी योजनाओं को समझने की कमी है। इन महिलाओं (N=236) 28% के पास शौचालय नहीं है, 31% महिलाएं बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार हैं,

28% महिलाएं 18 वर्ष पूर्व बच्चे को जन्म दे चुकी थी, 23% महिलाएं प्रसव के दौरान स्वास्थ्य की जांच नहीं कराती और 25% महिलाओं का पहला प्रसव घर पर ही हुआ। परेशानी यह भी रेखांकित की गई कि 31% महिलाओं को घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दूसरे घरों में काम करना पड़ रहा है। इससे 31% महिलाओं ने बताया कि उनका शोषण शारीरिक और आर्थिक रूप से घर मालिक परिवारों द्वारा होता है। टिफिन कैरियर का धंधा सूरत में खत्म हो गया। 350 रेस्टोरेंट में से 30% ही चालू है। जो महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से काम करती थी अब उन्हें घर पर बैठना पड़ रहा है। विश्व बैंक द्वारा मास्क एवं पीपीई बनाने में स्व सहायता समूह की आमदनी तथा उन्हें रोजगार सृजन का नया अवसर दिया है। भोजन तैयार करके वितरण हेतु सामुदायिक किचन का नया उद्यम कोरोना संक्रमण में लिया गया।

उड़ीसा राज्य में स्व–सहायता समूह ने सैनिटाइजर बनाने, मास्क बनाने तथा पीपीई किट तैयार करने के अलावा स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के कार्य संभाला हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 750 मिलियन डॉलर का ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। कुटुंब श्री स्व–सहायता समूह से 4.4 मिलियन महिलाएं जुड़ी हैं, जो 13,100 सामुदायिक किचन से तैयार भोजन का भार समूह उठा रही हैं। बिहार में जीविका संगठन द्वारा कोविड–19 के प्रति सावधानी और सुरक्षा हेतु पोस्टर, हाइजीन, मोबाइल संदेश, हैंडवाश की तैयारी और वितरण तथा क्वारन्टीन केंद्रों में भोजन सप्लाई जैसे काम महिला समूहों को दिए गए हैं। महिलाओं को हेल्पडेस्क और पीड़ित प्रवासी परिवारों की मदद में झारखंड राज्य की महिला समूहों को लगाया गया है।

आजीविका पर संकट भारत के 40 करोड़ प्रवासी मजदूर जनसंख्या पर सीधे तौर पर पडा है, और व्यापक प्रभाव आकलन यह है कोरोना वायरस के प्रसार से पहले ही आर्थिक मंदी आ चुकी थी। इसकी वजह से देश के मध्यम वर्ग तक की क्रय क्षमता बिगड़ रही थी। यदि आर्थिक सुधार लॉकडाउन के बाद भी धीमे रहे, तो आम परिवारों को इसका जोखिम और अधिक होगा और खपत में ज्यादा कटौती करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परिवारों की वित्तीय स्थिति का आंकड़ा सार्वजनिक किया है। आम परिवारों को बैंक में धनराशि जमा कराने का रुझान पहली तिमाही में कमजोर पड़ा है। 2019–20 में विशुद्ध वित्तीय बचत सकल घरेलू उत्पाद के 7.7% स्तर पर रही जबकि इसके पिछले वर्ष में यह 7.2% थी, क्योंकि आम परिवारों ने बैंकों से कर्ज कम लिए थे। सकल वित्तीय बचत भी घटकर जी.डी.पी. की तुलना में 10% रह गई थी, जबकि इससे पिछले वर्ष यह 11.1% थी, (बिजनेस स्टेण्डर्ड, 21 जून, 2020)

आकलन है कि आम घरों में वित्तीय बचत की उच्च उपलब्धता निजी क्षेत्र में कमजोर ऋण मांग राजकोषीय घाटे की भरपाई में सहायक हो सकती है। सरकारों का बजट घाटा चालू वर्ष में बढ़ सकता है। हालात में बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि हम वायरस पर कितनी तेजी से नियंत्रण कर पाते हैं। अब महिलाओं की आत्मनिर्भरता का रास्ता ढूंढने तो स्व–सहायता समूह से बड़ी उम्मीदें हैं तथा उन्हें गरीबी के घेरे में परिवारों में आर्थिक जिम्मेदारी को परखना होगा। देश का सकल घरेलू उत्पाद और अन्य संकेतकों का भी संबंध महिलाओं के आर्थिक भागीदारी से है, जिनकी महामारी के संकट काल में गणना करने की आवश्यकता होगी।

सुझाव एवं निष्कर्ष

कोविड–19 महामारी 'आपदा' के रूप में महामारी का प्रभाव दिखा रही है। भारत में एक लाख से अधिक जनहानि हुयी। अर्थव्यवस्था में गिरावट लगातार है तथा बचत और राजस्व दोनों क्षेत्र में कमी। महिलाओं का जीवन संकट में घिर गया है। प्रवजन का दबाव, बेकारी, बेरोजगारी का असर लॉकडाउन में सबको भय और आशंका का शिकार होना पड़ा है। इससे गरीब महिलायें सर्वाधिक प्रभावित हैं। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में महिला रोजगार की स्थिति गिरावट की ओर है। सफेद पोष शहरी पेशे में महिलायें काम से बाहर होती जा रही है। बड़ी–बड़ी नौकरियॉ एक झटके से जा रही हैं। संक्रमण का परिवार स्तर पर फैलाव से भी घरों के बाहर काम का परहेज किया जा रहा है। घरों के बाहर काम से परहेज किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार और उनकी महिलायें संक्रमण पीड़ित जल्दी जल्दी हो रही हैं।

पिछले 8 महीनों में हालात महामारी, संक्रमण के कम नहीं हुये हैं। वैक्सीन का आना सबकी चिंता के समाधान का एक उपाय होगा। ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण कोविड–19 का बढ़ने का आकड़ा मिला है। ऐसे हालात में ग्रामीण महिलाओं की चिंता करनी जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *इकोनॉमिक्स टाइम्स, अप्रैल 26, 2020*
2. *इण्डिया वाटर पोर्टल, 13 अप्रैल, 2020 कमजोर वर्ग पर महामारी का अधिक प्रभाव*
3. *इण्डिया टुडे, 17 जून, 2020 पर्दे के पीछे, अंशुमन तिवारी*
4. *बी.बी.सी. हिन्दी, 2 अप्रैल, 2020*
5. *बिजनेस स्टेण्डर्ड, जून 14, 2020, कम जॉच की समस्या*
6. *बिजनेस स्टेण्डर्ड, जून 16, 2020, कोविड लॉकडाउन और सफलता की परिभाषा*
7. *बिजनेस स्टेण्डर्ड, जून 16, 2020, जॉच की रणनीति*
8. *बिजनेस स्टेण्डर्ड, जून 18, 2020, अनलॉक और आर्थिक संकट,*
9. *बिजनेस स्टेण्डर्ड, जून 19, 2020, जीने की जद्दोजहद*
10. *बिजनेस स्टेण्डर्ड, जून 21, 2020*
11. *न्यूज क्लिक, 3 अप्रैल, 2020*
12. *न्यूज क्लिक, कोरोना महामारी और महिलाओं पर बढ़ती हिंसा*
13. *दैनिक भास्कर, 14 जून, 2020*
14. *दैनिक भास्कर न्यूज, 22 जून, 2020*
15. *"Women at the centre of development has been an important story in South Asia. In these extra ordinary times, when we are all united in our fight*

against the Covid-19 Virus, these womens groups are playing a critical role."…… Junaid Ahmed, World Bank India Office.

16. *Across the country womens SHG have risen to this extraordinary challenges with in mense courge and dedication." …….. Alka Upadhaya, Additional Secretory, Ministry of Rural Development India.*
17. *Aditi Rathor & Soumya Bhomik, East to West India's migrants crisis looms large during Covid-19, Health Express, April 20, 2020. www.theatlamtic.com*
18. *Agribuzz, Impact of Covid-19 on Women Working in the domestic Sector in Hyderabad, May 1st, 2020.*
19. *Ahmed K.Sedati, et.al., Risk Society Global Vulnerability and Fragile Resilience, Shiraz-E-Medical Journal, March, 2020.*
20. *businessworld.in, Impact of covid-19 and Indian economy and Road ahead for 30 April, 2020*
21. *economictimes.com, Coronavirus impact on Economy : Pon Review impact of Covid, 16th April, 2020*
22. *Elisa Matrinuzzi, Looking at the Pendemic through Gender Women are facing the brought of Covid-19 with mode Job Cuts, Less Pay. Economic Times, 10.06.20.*
23. *En.Wikipedia, Economic impact of the covid-19 pandemic in India.*
24. *In over 90% of India's district, away from the limelight of the cities SHG women are producing facemasks, running community kitchens, delivering essential food supplies, sensitizing people about health and hygine and combating misinformation." ……World Bank, 2020*
25. *Indian Express, Explain how covid-19 has affected the global economy 16th May, 2020*
26. *KMPG Insights : The business implication of coronavirus, 5th May, 2020*
27. *Living with Covid-19, EPW, 16th May, 2020*
28. *Martha Henrics, BBC News Hindi, 4th May, 2020*
29. *P.Patnaik, Microeconomics of a lockdown. EPW, 12th Sept, 2020.*
30. *Paul R.Wood, A Sociology of the Covid-19 Pandemic : A commentary and research agenda for sociologist.*
31. *Ranjeeta Mohanty, Migrant workers and the dark underbelly of urban economy. www.citizen.in 9th April, 2020.*
32. *Steve Mathewan & Kate Hupptaz (2020), A Sociology of Covid-19, Journal of Sociology-1(9).*
33. *UNCTAD.*
34. *Unmilan Kalita et.al.(2020), Economic implication of a Novel disease outbreak, EPW, 13th June,2020.*
35. *World Bank Feature Story, April 11th, 2020*
36. *www.businessstandard, Covid-19 impact of Indian economy to shrink by 3.2% in F.Y. 2021, 9th June, 2020*
37. *www.firstpost.com, Covid-19 lockdown impact fitch rating says Indian, 27th May, 2020*
38. *www.idea.org, Covid-19 infection the Indian economy, S.M.Dev*
39. *www.Insight impact of covid-19 on Indian economic, 4th April, 2020*
40. *www.location.today.co.in, Potential impact of Covid-19 on the Indian economy, April-2020.*
41. *www.magzter.com, Covid-19 its impact and opportunity for Indian economy, May, 2020*
42. *www.mondaq, Corona Virus (Covid-19) and Indian economy, 19th May, 2020*
43. *www.navjivanindia.com, Mahendra Pandey, 29th March, 2020.*
44. *www.statistia.com, Impact of the coronavirus on Indian economy, 28 April, 2020*